

संक्षिप्त समाचार

पटना के कोचिंग सेंटर में हुई गोलीबारी मामले में खान सर को राहत

पटना। बिहार के पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी मामले में मशहूर यूट्यूब शिक्षक खान सर (फैसल खान) को राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने खान सर द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांचकर्ता खान से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन अंतरिम सुरक्षा लागू रहने तक उनकी गिरफ्तारी सहित कोई भी दंडात्मक या जबरदस्ती कार्रवाई नहीं हो सकेगी। पटना के मुसलहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून को रात 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके पास के कोचिंग संचालक ने यह हमला करवाया है। इसके बाद पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रीशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

राजस्थान में जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बच्चे समेत 3 की मौत

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई है। हादसा खोह नागरियान इलाके में स्थित फैक्ट्री में हुआ है। आग ने फैक्ट्री के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 6 से अधिक मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। मौके पर अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। खोह नागरियान थाना क्षेत्र के आयाशा नगर तलाई क्षेत्र में यह पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इसके आसपास रिहायशी बस्ती बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फैक्ट्री को रिहायशी इलाके में चलने की अनुमति कैसे मिली। आग लगने के कारणों की भी जांच शुरू कर दी है। हालांकि, किसी प्रकार के घमाके की आवाज नहीं सुनी गई, जिससे पटाखों में विस्फोट होने की बात भी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैक्ट्री में आग लगने के बाद झुलसे मजदूर बचकर निकल आए और काफी समय तक सड़कों पर ही तड़पते मिले।

नशे के लिए घुली हुई पेनकिलर का इंजेक्शन लगाने से युवती की मौत

त्रिची। तमिलनाडु में नशा करने के लिए दर्दनिवारक इंजेक्शन (पेनकिलर का इंजेक्शन) लगाने के बाद एक 18 साल की महिला की मौत हो गई। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है। त्रिची के अरियामंगलम में एमअर मिल स्ट्रीट को एक 18 साल की युवती ने 7 जून की रात लगभग 9:30 बजे उसी इलाके के एक 19 साल के दोस्त को लेकर त्रिची जंक्शन के पास एक निजी लॉज में गई थी। खबर के मुताबिक, कल दोपहर लगभग 1:00 बजे, उसके दोस्त ने एक अन्य दोस्त को लॉज में बुलाया, जहां वे दोनों ठहरे हुए थे।

इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ नाम

4399 दिन तक पीएम रहने वाले पहले नेता बने पीएम मोदी

नई दिल्ली/ एजेंसी

पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया। इस मौके पर पीएम मोदी भारत मंडपम से अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इतने लंबे समय तक 'भारत माता' की सेवा करना और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, केवल ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव है। और मेरे लिए, जनता ही ईश्वर का रूप है, इसलिए मैंने हमेशा इस सेवा को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा है। यह आध्यात्मिक साधना कभी

भी अकेले नहीं रही; यह एक सामूहिक 'यज्ञ' है, जिसमें आप सभी और कई अन्य सहयोगियों ने कर्तव्य की भावना के साथ अपना योगदान दिया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की जनता का नीर-क्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जर्नादन की परिपक्वता ही है कि मुझे लंबे समय तक इस पद पर रखा है। अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है। जनता जर्नादन का आभार व्यक्त करता हूं। साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का संरक्षण हम सभी का बड़ा दायित्व था। देश के



लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। उन्होंने कहा, आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। ये देश के जन-जन का सपना और संकल्प बन चुका है। एनडीए के 12

वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद है। कांग्रेस ने देश को लाचारी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुर्पई से धोमी विकास को एक नाम दिया था- हिंदू ग्रोथ रेट। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था- कांग्रेस ग्रोथ रेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहली बार जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ों रुपये के घोटालों में घसीट दिया। देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी।

कांग्रेस ने देश को लाचारी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था: पीएम

एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुर्पई से धोमी विकास को एक नाम दिया था 'हिंदू ग्रोथ रेट' यानी कार्यशैली कांग्रेस की, वास्तव कांग्रेस का, शिफारत कांग्रेस की लेकिन कलक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में न सुशासन था, न नीति, न नीयत और ना निर्णय। फली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

ईसी से निराश कांग्रेस अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। बैठक में मध्य प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक राष्ट्रपति दीपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले बुधवार



को कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल में कैसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल और विवेक तन्खा समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे।

मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल पर महासंग्राम!

एक तरफ तारीफों के पुल,दूसरी तरफ‘बर्बादी’ का आरोप-राहुल

नई दिल्ली/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,399 दिनों तक लगातार सेवा देते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी के साथ एनडीए सरकार के भी 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर पक्ष उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहा है। तो दूसरी तरफविपक्ष मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी के कामों को बर्बादी करार दे रहा है। इस पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी



किया है। इस पोस्टर में कांग्रेस ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था के बुरे हाल पर कटाक्ष किया है। इस पोस्टर में मोदी के 12 साल के कुप्रबंधन का लेखा-जोखा बताया। मोदी ने अपने पोस्टर के माध्यम से कहा कि पीएम मोदी ने 12

हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग,10 दुकानें चपेट में

रोहतक। हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई है जिसने नजदीकी 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस बीच करीब 6 लोगों की आग के अंदर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। रोहतक में डी-पार्क के पास स्थित जूते के शोरूम में मंगलवार दोपहर करीब 1.30 बजे भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग ने देखते ही देखते आसपास की 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. आग से निकल रहे धुएँ के गुबार को काफी दूर से देखा जा सकता है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 2 बजे मौके पर पहुंचीं।

ममता को अबतक का सबसे बड़ा झटका

बागी सांसदों की लिस्ट में सबसे खास सयानी घोष का नाम

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राज्य की सत्ता से बाहर हुई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। टीएमसी चीफममता बनर्जी को हर दिन नये झटके लग रहे हैं। अब जो खबर निकलकर सामने आई है, उसे ममता बनर्जी को लगा को अबतक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता बनर्जी को बेहद करीबी और टीएमसी की निजी लॉज में गई थी. खबर के मुताबिक, कल दोपहर लगभग 1:00 बजे, उसके दोस्त ने एक अन्य दोस्त को लॉज में बुलाया, जहां वे दोनों ठहरे हुए थे।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सयानी घोष ने भी हस्ताक्षर है। यह ममता बनर्जी के लिए अबतक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद सयानी घोष टीएमसी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी तक कहा जाता रहा है। सयानी घोष पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री, गायिका और तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके गाए गाने 'मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीनात काफी चर्चा और विवाद में रहा था। बीजेपी नेताओं ने गाने को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया



था और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे। तृणमूल कांग्रेस में बगावत का दौर रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा के निष्कासन के बाद शुरू हुआ था। पार्टी विरोध गतिविधियों के चलते ममता ने इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया

सांसदों ने बगावत करते हुए अलग गुट बना लिया है। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद एक अलग गुट बनाकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं बागी सांसदों ने काकोली घोष को अपना चीफ व्हिप चुना है। हालांकि अभी तक जो नाम सामने आए हैं, उसमें टीएमसी के 14 सांसद हैं। काकोली घोष के साथ में शताब्दी राय, बापी हलदर, अरूप चक्रवर्ती, जून मालिया, दीपक अधिकारी (देव), कालीपदा सेरेन, जगदीश बसुनिया, अमित मल, अबू ताहिर खान, खलीकुर रहमान, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी और पार्थ भूमिक हैं। अब इस लिस्ट में सयानी घोष का भी नाम शामिल हो गया है।

टीएमसी को लगा बड़ा झटका! सांसद सुष्मिता देब ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा

टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देब ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। एक हफ्ते के अंदर-अंदर दूसरे सांसद का इस्तीफा सामने आया है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा से इस्तीफा देते ही उनकी अराम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता किमंत बिरसा सरमा से मुलाकात की बात सामने आई है। इस मुलाकात ने कई अटकलें को जन्म दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार उन्हें अराम से राज्यसभा सीट का औचित्य दे सकती है। अब सभी की नज़रें सुष्मिता देव और किमंत बिरसा सरमा की मुलाकात पर टिकी हुई हैं।



पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा। आवेदक के पालक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र के साथ कक्षा 4वीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयकरदाता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा विद्यालय के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने का प्रमाण पत्र संलग्न 20 जून 2026 तक अपनी शाला जमा कर सकते हैं। योजना संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र के लिए संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

पुलिस शिकायत का बदला लेने
साले ने जीजा के घर लगाई में
आग, पहुंचा सलाखों के पीछे

रायपुर। पारिवारिक विवाद ने उस समय
गंभीर रूप ले लिया जब पुलिस में शिकायत दर्ज
कराने से नाराज एक युवक ने अपने ही जीजा के
घर को आग के हवाले कर दिया। मामले में
त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को
गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे
जेल भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी
के अनुसार, घटना 6 जून की है। पीड़ित अपने
मोहले में बैठा हुआ था, तभी उसका साला रिस्ता
नेताम शराब के नशे में वहां पहुंचा और गाली-
गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने
हाथ-मुर्कों से मारपीट की और गाल पर नुकीली
वस्तु से हमला कर उसे घायल कर दिया। मारपीट
की शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित चौकी
चिखली पहुंचा। इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में
आकर उसके घर में आग लगा दी।

शराब छोड़ने की नसीहत
पड़ी भारी, बहू ने ईंट से
फेंड़ दिया ससुर का सिर

रायपुर। परिवार के भीतर हुई मामूली
कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। स्मृतिनगर
पुलिस चौकी क्षेत्र में एक बहू ने अपने ही ससुर
पर ईंट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर
दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, बीती रात महिला शराब का
सेवन कर रही थी। इसी दौरान उसके ससुर ने
शराब पीने से मना करते हुए समझाइश दी। ससुर
की यह बात बहू को नागवार गुजरी और वह गुस्से
में आगबबूला हो गई। आरोप है कि नशे की
हालत में उसने पास में रखी ईंट उठाई और ससुर
पर लगातार बार कर दिए। हमले में बुजुर्ग के सिर
पर गंभीर चोट आई। शोर-शराबा सुनकर
आसपास के लोग बीच-बचाव के लिए पहुंचे,
लेकिन बहू ने उनके साथ भी मारपीट कर दी।
किसी तरह लोगों ने स्थिति को नियंत्रित किया
और घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां
उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते
ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच
शुरू कर दी।

जेल के 4 बंदी एचआईवी संक्रमित,
स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

रायपुर। जिले की जिला जेल से सामने आई
एक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ने प्रशासन और
स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिला
अस्पताल में कराई गई जांच के दौरान जेल में बंद
चार कैदियों की रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आई
है। इसके बाद जेल प्रशासन और स्वास्थ्य अमला
आवश्यक उपचार एवं निगरानी व्यवस्था में जुट
गया है। जानकारी के अनुसार, संक्रमित पाए गए
बंदियों को जेल अस्पताल के माध्यम से नियमित
दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही
समय-समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी
कराया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर उन्हें
बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में विशेषज्ञ
जांच और परामर्श के लिए भेजा जाता है।
एचआईवी संक्रमण की पुष्टि के बाद जेल प्रशासन
ने बंदियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर
दी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि
संक्रमण कब और किन परिस्थितियों में हुआ, यह
जांच का विषय है।

तेज रफ्तार कार की टक्कर
से युवक की मौके पर मौत

रायपुर। राजधानी में तेज रफ्तार वाहनों का
कहर धमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकर नगर
इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक
सवार युवक की जान चली गई। हादसा बर्गर
किंग के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने
बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मिली जानकारी
के अनुसार, मृतक की पहचान लाखेनगर निवासी
उदय रगड़े के रूप में हुई है। वह अपने काम से
शंकर नगर क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज
गति से आ रही कार ने उसकी बाइक को टक्कर
मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की
रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद युवक
सड़क पर दूर जा गिरा और उसने मौके पर ही दम
तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों
की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल
पुलिस को सूचना दी।

फल दुकान संचालक पर चाकू से
जानलेवा हमला करने वाला आरोपी
गिरफ्तार

रायपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस
प्रकार है कि दिनांक 07.06.2026 की रात्रि
लगभग 09:30 बने प्रार्थिया द्वारा थाना सिरगिट्टी
में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका पति मनीष
गोस्वामी अपनी फल दुकान के पास खड़ा था।
उसी दौरान आरोपी दुर्गेश साहू उर्फ गोल्डू सफिंट
वहां पहुंचा और पीछे से पकड़कर हल्ला करने की
नीयत से अपने पास रखे धारदार चाकू से हमला
कर फरार हो गया। घटना में घायल की गंभीर चोटों
आने पर थाना सिरगिट्टी में अपराध क्रमांक
409/2026 धारा 103, 115(2) बीएनएस के तहत
अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले
की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सिरगिट्टी
निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा विशेष टीम गठित कर
आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई।

सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ

अब एक कॉल पर सुनी जाएगी
जनता की हर समस्या-साय.....

- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा – सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलेगी नई मजबूती
 - 42 विभागों के 8 हजार अधिकारी 1195 श्रेणियों में शिकायतों का करेंगे समयबद्ध निराकरण
- रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य की बहुप्रतीक्षित सीएम हेल्पलाइन 1076 का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगों का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री



साय ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या सुनी जाए, उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शासन-प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर से प्राप्त शिकायतों, सुझावों और जनप्रतिपाद ने एक प्रभावी, सशक्त एवं स्थायी जनसंपर्क तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी सोच के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर

आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपने व्यापक दायरे के कारण विशेष महत्व रखती है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। यदि किसी शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से संतोष नहीं होगा, तो संबंधित शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण एवं जांच के लिए अग्रेषित हो जाएगी। इससे शिकायतों के सतही निराकरण की संभावना समाप्त होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगी। इसके संचालन के लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर
कम लागत में बढ़ा रहे उत्पादन.....

- नैनो यूरिया से आसान हुई खेती, किसान गुलाबचंद राठौर को मिल रहे बेहतर परिणाम
 - नैनो उर्वरकों के उपयोग से उर्वरक प्रबंधन हुआ सरल, समय और श्रम की हो रही बचत
- रायपुर/ संवाददाता

राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब किसानों के खेतों में दिखाई देने लगा है। आधुनिक कृषि तकनीकों एवं नवाचारों को अपनाकर किसान

खेती को अधिक सुविधाजनक, किफायती और लाभकारी बना रहे हैं। सक्ती जिले के विकासखंड सक्ती अंतर्गत ग्राम अचानकपुर के प्रगतिशील किसान श्री गुलाबचंद राठौर भी ऐसे ही किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने नैनो यूरिया (तरल) का सफल उपयोग कर खेती में बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं तथा अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री गुलाबचंद राठौर ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष अपनी कृषि भूमि में नैनो यूरिया का उपयोग किया था, जिसके परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक यूरिया की 45 किलोग्राम की भारी बोहरियों की तुलना में नैनो यूरिया का परिवहन, भंडारण एवं उपयोग कहीं अधिक सरल और सुविधाजनक है। इसकी छोटी शीशी को किसान आसानी से खेत तक ले जा सकते हैं, जिससे समय, श्रम और परिवहन व्यय में उल्लेखनीय बचत होती है।

मोदी युग के 12 वर्ष राष्ट्र गौरव

आर्थिक प्रगति और विकसित भारत
की स्वर्णिम युग-रामविचार नेताम...

रायपुर/ संवाददाता

आदिम जाति विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए 10 जून 2026 एक ऐतिहासिक अवसर है। इस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यह केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के अटूट विश्वास, जनसमर्थन और राष्ट्रहित में समर्पित नेतृत्व की गौरवगाथा है। एक साधारण परिवार से निकलकर



देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद तक पहुंचने की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा करोड़ों भारतीयों के सपनों के अमूर्तपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना जैसी पहलों ने करोड़ों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। वहीं जनजातीय समाज को सम्मान दिलाने, भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को राष्ट्रीय पहचान देने तथा वर्नाचल क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए कार्य उनकी संवेदनशील सोच को दर्शाते हैं।

595 बिल्डरों को नोटिस, 989
परियोजनाओं में प्रबंधन
हस्तांतरण नहीं करने का आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने प्रदेशभर के 595 बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। इन बिल्डरों पर आरोप है कि आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद भी उन्होंने कॉलोनियों और परिसरों का प्रबंधन आर्बिट्रियर्स की समिति या संघ को हस्तांतरित नहीं किया। रera की कार्रवाई के दायरे में रायपुर के अविनाश ग्रुप, सिंघानिया बिल्डरकॉन, वालफेर्ट सहित कई प्रमुख बिल्डर आए हैं। नोटिस रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा समेत विभिन्न जिलों की कुल 989 परियोजनाओं के संबंध में जारी किए गए हैं। रera के अनुसार, नियमों के तहत परियोजना पूर्ण होने और नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद बिल्डरों को सामान्य क्षेत्र, सुविधाएं, अभिलेख और प्रबंधन का हस्तांतरण रहवाशियों की समिति अथवा संघ को करना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई परियोजनाओं में अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। प्राधिकरण ने बताया कि कई मामलों में परियोजना पूर्ण होने के बाद भी आर्बिट्रियर्स की समिति का गठन नहीं कराया गया।

प्रतिभा, परंपरा और सृजनशीलता का उत्सव

रंग,रचनात्मकता और संस्कृति का महोत्सव बना आकार-2026



अतिथि सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2004 में संस्कृति मंत्री रहते हुए उन्होंने आकार प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवंत

अब ई-रिक्शा से
आत्मनिर्भर बनेंगी
श्रीमती अघन्तीन

रायपुर। सुशासन तिहार के वर्ष पुराना श्रम पंजीयन था, जो तहत श्रम विभाग की ई-रिक्शा सहायता योजना ने ग्राम चरकई निवासी अघन्तीन नेताम के जीवन में नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता की राह खोल दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों ई-रिक्शा प्राप्त करते ही अघन्तीन के चेहरे पर आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की झलक साफ दिखाई दी। अघन्तीन नेताम पहले अपने परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करने के लिए दैनिक मजदूरी (रेजा-कुली) का कार्य करती थीं। सीमित आय और काम की अनिश्चितता के कारण परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं। इसी दौरान उनके छोटे भाई को श्रम विभाग द्वारा संचालित ई-रिक्शा सहायता योजना की जानकारी मिली। उन्होंने अघन्तीन को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अघन्तीन का श्रम विभाग में तीन वर्ष पुराना श्रम पंजीयन था, जो योजना की पात्रता की प्रमुख शर्तों में शामिल है। इसके अलावा ई-रिक्शा संचालन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक के माध्यम से वाहन फाइनेंस की प्रक्रिया भी आवश्यक थी। अघन्तीन ने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उन्हें डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त हुई और ई-रिक्शा उपलब्ध कराया गया। अब यह ई-रिक्शा उनके लिए रोजगार का स्थायी साधन बनकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अघन्तीन का कहना है कि अब वे स्वयं की मेहनत से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और अपने माता-पिता की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहयोग करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा मिलने से उन्हें नियमित आय का अवसर मिलेगा, जिससे वे सम्मानजनक और स्वावलंबी जीवन जी सकेंगी।



धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 490.818 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मामले में चार आरोपियों समेत एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा गया। कार्रवाई में तस्करों में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, पिकअप वाहन और मोबाइल फोन भी जब्त हुए।

गैंगरेप मामले में सिलयारी
चौकी का स्टॉफ दोषी.....

रायपुर। संवाददाता

रायपुर जिले के धरसीवा क्षेत्र की सिलयारी चौकी से जुड़े नाबालिग गैंगरेप मामले में चौकी प्रभारी जितेंद्र दुबे को निर्लंबित कर दिया गया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच को लेकर सवाल उठने के बाद यह कदम उठाया गया। साथ ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। कांग्रेस ने इस मामले में पूरी सिलयारी चौकी का स्टॉफ को दोषी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की है। कांग्रेस भवन में एक पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष राजेंद्र पणू बंजारे ने बताया कि 18 अप्रैल की घटना है। घटना के बाद इस मामले में लीपोती का

लगातार प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने बताया कि नाबालिग बालिका के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पहले गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किए जाने और जांच में लापरवाही के आरोप लगे थे। इसके विरोध में कांग्रेस ने धरसीवा क्षेत्र में आंदोलन किया, पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग उठाई। बढ़ते जनदबाव के बीच प्रशासन ने चौकी प्रभारी को निर्लंबित किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया है और विपक्ष इसे कानून-व्यवस्था तथा पुलिस की कार्यप्रणाली से जोड़कर उठा रहा है।

- 16 विधाओं में 1281 प्रतिभागियों ने लिया प्रशिक्षण, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ भव्य समापन
 - नई पीढ़ी को संस्कृति, कला और लोक परंपराओं की जानकारी देना समय की आवश्यकता है
- रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और आधुनिक रचनात्मकता के अद्भुत संगम का प्रतीक बना संस्कृति विभाग का बहुप्रतीक्षित कला प्रशिक्षण

शिविर आकार-2026 रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतिभागियों की शानदार प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हो गया। 25 मई से 9 जून तक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, रायपुर में आयोजित इस 16 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेशभर से आए 1281 प्रतिभागियों ने 16 विभिन्न कला विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को नई दिशा दी। समापन समारोह में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रभात मिश्रा, छत्तीसगढ़ फ़िल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौज तथा उप संचालक श्री प्रताप चंद्र पारख सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी, प्रशिक्षु एवं अभिभावक उपस्थित थे। मुख्य

बनाए रखने तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह पहल प्रारंभ की गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ऐसे आयोजन प्रदेश के सभी संभागों में आयोजित किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के

पारंपरिक आभूषणों, हस्तशिल्प के लिए स्थायी विक्रय केंद्र भी विकसित किए जाने चाहिए, जिससे कलाकारों को आर्थिक लाभ मिल सके और लोग छत्तीसगढ़ के आभूषण और हस्तशिल्प को देख और खरीद सकें। श्री अग्रवाल ने बच्चों को मिट्टी और प्रकृति से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जिस दिन बच्चे मिट्टी से जुड़ना और मिट्टी से सृजन करना सीख जाएंगे, उनका जीवन आनंद और संवेदनशीलता से भर जाएगा। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं की जानकारी देना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के स्वागत उद्घोषण में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौज ने कहा कि आकार केवल एक प्रशिक्षण शिविर नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककलाओं, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धित करने का एक सशक्त माध्यम है।

संपादकीय

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियोुक्तिक के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है।विचित्र बात है कि विवाह के बाद समाज बेटीयों को परिवार से अलग मान लेता है। जबकि बेटीयां माता-पिता के प्रति अपना

दायित्व बखूबी निभाती हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करती हैं। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में वे आश्रित भी रहती हैं। ऐसे में परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल न करना न केवल समानता के सिद्धांत के विपरीत, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है।गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए बीते मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने व्यवस्था दी कि

बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियोुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता और परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल न करना मनमाना, अनुचित तथा संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियोुक्ति के

उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है।इस पर एक मृत राशन विक्रेता की बेटी ने आदेश को चुनौती दी, जिसमें अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के डीलर के रूप में नियोुक्ति के उसके दावे को खारिज कर दिया गया था।इस परिप्रेश्य में शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि विवाह न तो बेटी और माता-पिता के बीच बंधन को समाप्त

करता है और न ही आश्रित नहीं होने का वैध आधार प्रदान करता है। दो मत नहीं कि परिवार में बेटे-बेटियों के समान अधिकार हैं। इसे स्वीकार करना होगा और बेटियों के अधिकारों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अदालत का यह कहना उचित है कि निर्भरता एक तथ्यात्मक प्रश्न है। इसका निर्णायक निर्धारण नहीं किया जा सकता।निस्संदेह परिवार की परिभाषा में

वैवाहिक स्थिति से ऊपर उठकर परस्पर निर्भरता को भी समझने की जरूरत है। इसे इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि जब एक विवाहित पुत्र परिवार का हिस्सा होता है, तो विवाहित बेटी से किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? शीर्ष न्यायालय ने इसी असमानता को दूर करने का संदेश दिया है। इससे बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा एक बार और सुनिश्चित हुई है।

आखिर कैसे रूकेंगे मालवीय नगर होटल अग्निकांड जैसे हादसे, जिम्मेदार कौन?

(कमलेश पांडे)

स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय- अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक उपयोग और सुरक्षा उल्लंघनों की समय रहते पहचान न कर पाना भी जांच का विषय है। चूंकि स्थानीय प्रशासन और नगर निकाय से जुड़े जिम्मेदार लोग भी यदि समय रहते हो खामियां पकड़ लिए होते और स्पष्ट कार्रवाई किये होते तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की इतनी बदनामी नहीं होती।

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल- अग्निकांड में 21 लोगों की मृत्यु और दर्जनों के घायल होने को घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा नियमों की संभावित विफलता और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली या अन्य महानगरों में ऐसे इसी हो घटनाओं से सिविल/पुलिस प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली, जिससे यह हादसा भी नियति का खेल बनकर रह गया। प्रशासन को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, जिससे इतनी भारी क्षति नहीं हो जाए।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भवन में केवल एक प्रवेश-निकास मार्ग था, बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों में क्षमता से अधिक कमरे संचालित किए जा रहे थे, तथा अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन पर भी सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा यह प्रश्न मौजू है कि आखिर इस लोमहर्षक और दर्दनाक घटना का जिम्मेदार कौन? यह ठीक है कि जांच पूरी होने से पहले अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसी घटनाओं में जिम्मेदारी कई स्तरों पर तय होती है जो इस प्रकार से समझी जा सकती है-

पहला, होटल मालिक और अदृशदशी प्रबंधन- यदि बिना वैध अग्नि सुरक्षा अनुमति के संचालन हुआ। यदि निर्धारित क्षमता से अधिक कमरे या अवैध निर्माण किए गए। यदि आपातकालीन निकास, अलार्म और अग्निशमन उपकरण रक्षित नहीं थे। तो इस्त्का सीधा तात्पर्य है कि होटल मालिक के अदृशदशी प्रबंधन ने लोगों को अप्रत्याशित मुसीबत की आग में झुलसने को मजबूर कर दिया और समय पर समुचित मदद उपलब्ध नहीं पहुंच पाई। यह जांच का विषय है और शायद इसी वजह से होटल मालिक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।

दूसरा, लाइसेंस और निरीक्षण देने वाली एजेंसियां- यदि नियमों के उल्लंघन के बावजूद संचालन जारी रहा। यदि नियमित निरीक्षण केवल कागजी तक सीमित रहे, तो लाइसेंस जारी करने और निरीक्षण देने वाली एजेंसियों पर उँगली उठनी स्वाभाविक बात है, क्योंकि इनकी लापरवाही या मिलीभगत से न केवल जान-माल की भारी क्षति हुई, बल्कि केंद्र व राज्य सरकार के गुणवत्ता हान

लोकतंत्र प्रहरी

संपादकीय

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियोुक्तिक के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है।विचित्र बात है कि विवाह के बाद समाज बेटीयों को परिवार से अलग मान लेता है। जबकि बेटीयां माता-पिता के प्रति अपना

दायित्व बखूबी निभाती हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करती हैं। हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति में वे आश्रित भी रहती हैं। ऐसे में परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल न करना न केवल समानता के सिद्धांत के विपरीत, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है।गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए बीते मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने व्यवस्था दी कि

बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियोुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता और परिवार की परिभाषा में उन्हें शामिल न करना मनमाना, अनुचित तथा संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियोुक्ति के

सुप्रीम कोर्ट ने बदल दी ‘परिवार’ की परिभाषा

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह संकट अधिक चिंताजनक है। यहां करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर है। खेत केवल अन्न नहीं उगाते, वे गांवों की अर्थव्यवस्था, परिवारों की उम्मीदें और समाज की स्थिरता को भी जीवित रखते हैं। जब तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच जाता है और लू के थपेड़े लगातार कई दिनों तक चलते हैं, तब सबसे पहले खेत प्रभावित होते हैं। मिट्टी की नमी समाप्त होने लगती है, फसलों का विकास रुक जाता है और उत्पादन में भारी गिरावट आने लगती है। विशेष रूप से धान जैसी फसलें अत्यधिक तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि भारत में धान की पैदावार पर बड़े खतरे की आशंका जताई गई है। भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कभी मार्च-अप्रैल तक सुहावना रहने वाला मौसम अब फरवरी के अंत से ही गर्म होने लगता है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। धरती जब सूरज के ताप से झुलसने लगे, तब केवल मौसम नहीं बदलता, जीवन का पूरा संतुलन डगमगाने लगता है। कभी जेट की दोषहर ऋतु का स्वाभाविक स्वभाव मानी जाती थी, मगर आज वही तपती दोषहर भीषण गर्मी का मौर्य बनती जा रही है। खेतों की नमी सूख रही है, नदियों का जल सिकुड़ रहा है, पेड़ों की हरियाली पीली पड़ती जा रही है और किसानों के चेहरे पर भविष्य की चिंता की गहरी रेखाएं उभर रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने जिस खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है, वह केवल तापमान बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आधार—कृषि और खाद्य सुरक्षा—पर मंडराता संकट है। लू चलना अब एक मौसमी घटना नहीं रही, बल्कि वह धीरे-धीरे समाज, रोजगार और मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था और आजीविका का सवाल है गर्मी

(नूपेंद्र अभिषेक नूप)

भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कभी मार्च-अप्रैल तक सुहावना रहने वाला मौसम अब फरवरी के अंत से ही गर्म होने लगता है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। धरती जब सूरज के ताप से झुलसने लगे, तब केवल मौसम नहीं बदलता, जीवन का पूरा संतुलन डगमगाने लगता है। कभी जेट की दोषहर ऋतु का स्वाभाविक स्वभाव मानी जाती थी, मगर आज वही तपती दोषहर भीषण गर्मी का मौर्य बनती जा रही है। खेतों की नमी सूख रही है, नदियों का जल सिकुड़ रहा है, पेड़ों की हरियाली पीली पड़ती जा रही है और किसानों के चेहरे पर भविष्य की चिंता की गहरी रेखाएं उभर रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने जिस खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है, वह केवल तापमान बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आधार—कृषि और खाद्य सुरक्षा—पर मंडराता संकट है। लू चलना अब एक मौसमी घटना नहीं रही, बल्कि वह धीरे-धीरे समाज, रोजगार और मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह संकट अधिक चिंताजनक है। यहां करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर है। खेत केवल अन्न नहीं उगाते, वे गांवों की अर्थव्यवस्था, परिवारों की उम्मीदें और समाज की स्थिरता को भी जीवित रखते हैं। जब तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच जाता है और लू के थपेड़े लगातार कई दिनों तक चलते हैं, तब सबसे पहले खेत प्रभावित होते हैं। मिट्टी की नमी समाप्त होने लगती है, फसलों का विकास रुक जाता है और उत्पादन में भारी गिरावट आने लगती है। विशेष रूप से धान जैसी फसलें अत्यधिक तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि भारत में धान की पैदावार पर बड़े खतरे की आशंका जताई गई है।

भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कभी मार्च-अप्रैल तक सुहावना रहने वाला मौसम अब फरवरी के अंत से ही गर्म होने लगता है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लू की तीव्रता हर वर्ष बढ़ रही है। इसका सबसे गहरा असर खेती पर पड़ रहा है। गेहूं की फसल समय से पहले पकने लगती है, दाने का आकार छोटा हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। धान की खेती में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन बढ़ती गर्मी और बारिश कम होने के

कारण जल संकट गहरता जा रहा है। जब खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता, तब किसानों की पूरी मेहनत कुछ ही दिनों में बर्बाद हो जाती है। पहले किसान मौसम के संकेतों को देख कर खेती की योजना बना लेते थे, लेकिन अब मौसम की अनिश्चितता ने अनुभव और परंपरा दोनों को चुनौती दे दी है। यही कारण है कि खेती धीरे-धीरे जोखिम भरा व्यवसाय बनती जा रही है।



अत्यधिक गर्मी के कारण दुनिया भर में करोड़ों कार्य घटे प्रभावित हो रहे हैं। भारत में यह स्थिति और गंभीर है, क्योंकि यहां बड़ी आबादी खुले वातावरण में काम करती है। खेतों, निर्माण स्थलों और फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जब गर्मी असहनीय हो जाती है, तब काम के घंटे घट जाते हैं और मजदूरी पर इसका असर पड़ता है। फिर इसका सीधा प्रभाव गरीब परिवारों की आय पर पड़ता है। गांवों की अर्थव्यवस्था में कृषि केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता का आधार भी है। यदि खेती लगातार नुकसान देने लगेगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा। किसान शहरों की ओर रोजगार की तलाश में जाएंगे, जिससे शहरी क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा।

पहले ही महानगर भीड़, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।

ग्रामीण भारत में खेती के साथ-साथ पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है-पशुपालन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण भारत में खेती के साथ-साथ पशुपालन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। अत्यधिक गर्मी के कारण पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। चारे और पानी की

घटती गई, तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। यह स्थिति केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश को खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती होगी। खाद्यान्न की कमी से कीमतें बढ़ेंगी, तो गरीब तबके पर बोझ बढ़ेगा और सामाजिक असमानता और गहरी हो सकती है।

इस संकट का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार लोग ही सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। गांवों के गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे उत्पादक पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत वही चुका रहे हैं। दूसरी ओर, दुनिया के विकसित देशों ने दशकों तक औद्योगिक विकास के नाम पर भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया। आज जब पृथ्वी गर्म हो रही है, तब उनका दुर्प्रणिाम विकासशील देशों को भुगतान पड़ रहा है। इसलिए जलवायु न्याय की चर्चा भी अब वैश्विक मंचों पर तेज हो रही है।

कुछ नीतियों में अब हमें व्यापक बदलाव करने होंगे। किसानों को मौसम की सटीक जानकारी, फसल बीमा और तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होगी। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली और प्राकृतिक खेती जैसे विकल्प भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि समाज को भी अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना होगा। अत्यधिक उपभोग, संसाधनों की बर्बादी और प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता ने ही इस संकट को जन्म दिया है। यदि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनकर नहीं चलेगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और कठिन हो जाएगा।

हमें यह समझना होगा कि धरती केवल संसाधनों का भंडार नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। खेतों की हरियाली केवल किसानों की नहीं, पूरे समाज के लिए जीवन है। यदि खेती संकट में पड़ेगी, तो शहर भी सुरक्षित नहीं रहेगे। भोजन की हर थाली खेतों से होकर गुजरती है और खेतों का भविष्य अब जलवायु परिवर्तन की आग में झुलस रहा है। यह समय केवल चिंतन का नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प का है। यदि आज भी दुनिया ने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले वर्षों में सूखी धरती और खाली खेत कठोर वास्तविकता बन सकते हैं। इसलिए, यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न है। धरती को बचाना अब कोई आदर्शवादी सपना नहीं, बल्कि जीवन को बचाने की अनिवार्य शर्त बन चुका है।

कमी से उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। मुर्गी पालन उद्योग भी तापमान बढ़ने से प्रभावित हो रहा है। गर्मी बढ़ने पर पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फलों और सब्जियों की खेती भी इस संकट से अछूती नहीं है। अधिक तापमान के कारण फल समय से पहले पक जाते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। सब्जियों को पैदावार घटने से बाजार में कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई आम लोगों की रसोई तक पहुंच जाती है।

भारत में चावल उत्पादन पर मंडराता खतरा भी चिंता का विषय है। चावल केवल एक फसल नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के भोजन का आधार है। पूर्वी भारत सबसे बड़ा धान उत्पादक क्षेत्र है। यदि यहां तापमान लगातार बढ़ता रहा और पानी की उपलब्धता

भागते हैं घुसपैटिये, भगाने वाला चाहिए, चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई

सबसे तेज और निर्णायक कार्रवाई इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। नई सरकार ने पहचान करे, पकड़ें और वापस भेजो नीति लागू कर पूरे प्रशासनिक ढांचे को सक्रिय कर दिया है। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और सिलीगुड़ी जैसे सीमावर्ती इलाकों में होल्डिंग सेंटर बनाये जा रहे हैं, जहां पकड़े गये घुसपैटियों को रखा जा रहा है। दक्षिण 24 परगना के कुलतली क्षेत्र से हवाल ही में अठारह बांग्लादेशी पकड़े गये, जिनमें छह बच्चे भी शामिल थे। पूछताछ में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे दलालों की मदद से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे और पिछले कई वर्षों से ईंट भट्ठों समेत विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे।

(नीरज कुमार दुबे)

हम आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर तो हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सैकड़ों बांग्लादेशी अपने देश वापसी के इंतजार में पॉकबैंड दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन उनके दस्तावेज, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक पहचान की जांच कर रहा है। भारत के सामने आज सबसे बड़ा संकट सुनियोजित जनसंख्या घुसपैठ का है। बंगाल से लेकर असम, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अवैध बांग्लादेशी घुसपैटियों का जाल जिस तेजी से फैलावा गया, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पहली बार देश के कई राज्यों में इस समस्या के खिलाफ जिस कठोर और समन्वित अभियान की शुरुआत हुई है, उसने साफ कर दिया है कि भारत अब घुसपैटियों और उनके संरक्षकों के प्रति नरमी दिखाने के मूड में नहीं है।

सबसे तेज और निर्णायक कार्रवाई इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। नई सरकार ने पहचान करे, पकड़ें और वापस भेजो नीति लागू कर पूरे प्रशासनिक ढांचे को सक्रिय कर दिया है। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और सिलीगुड़ी जैसे सीमावर्ती इलाकों में होल्डिंग सेंटर बनाये जा रहे हैं, जहां पकड़े गये घुसपैटियों को रखा जा रहा है। दक्षिण 24 परगना के कुलतली क्षेत्र से हवाल ही में अठारह बांग्लादेशी पकड़े गये, जिनमें छह बच्चे भी शामिल थे। पूछताछ में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वे दलालों की मदद से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे और पिछले कई वर्षों से ईंट भट्ठों समेत विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे थे।

हम आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर तो हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सैकड़ों बांग्लादेशी अपने देश वापसी के इंतजार में पॉकबैंड दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन उनके दस्तावेज, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक पहचान की जांच कर रहा है। बादुरिया और स्वरूपनगर के होल्डिंग सेंट्रों में सैकड़ों घुसपैटियों को रखा गया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इनमें से कई लोग बंगाल की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे और फर्जी पहचान पत्रों के सहारे

वर्षों से भारतीय व्यवस्था में घुस चुके थे। यह केवल सीमा पार करने का मामला नहीं, बल्कि भारत की प्रशासनिक संरचना में संंध लगाने की संगठित साजिश थी।

उपर, गुजरात में चल रहा ऑपरेशन डेल्टा हंट इस बात का उदाहरण बन गया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो तो घुसपैठ के नेटवर्क को जड़ से हिलाया जा सकता है। गुजरात पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान चलाकर पांच सौ एक अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया और सात सौ बयासी से



अधिक सँदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ को। अहमदाबाद, सूरत, भरुच और कच्छ जैसे औद्योगिक इलाकों में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि अधिकतर घुसपैटिये पहले बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए और फिर दलालों की मदद से गुजरात तक पहुंचे।

गुजरात पुलिस ने दूरसंचार आंकड़ों और साइबर विश्लेषण के आधार पर छह हजार से अधिक सँदिग्ध मोबाइल संपर्कों की सूची तैयार की। यह दिखाता है कि घुसपैठ अब केवल सीमा पार करने तक सीमित नहीं, बल्कि संगठित नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज और मानव तस्करी का विशाल कारोबार बन चुका है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल घुसपैटिये ही नहीं, बल्कि उन्हें पनाह देने वाले, रोजगार देने वाले और फर्जी कागजात तैयार करने वाले लोग भी कठोर कार्रवाई से नहीं

संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि असम में घुसपैटियों की पहचान, हिरासत और वापसी के लिए विशेष अभियान लगातार चलाये जा रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में भी अवैध प्रवासन को लेकर भारी चिंता उभर चुकी है। वहां छात्र संगठनों और स्थानीय समूहों ने साफ कहा है कि बाहरी घुसपैठ राज्य की सांस्कृतिक पहचान और जनजातीय अधिकारों के लिए खतरा बन रही है। राज्य पहले से इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत आता है, फिर भी स्थानीय समाज का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले सँदिग्ध लोगों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अरुणाचल सरकार ने जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाए और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में जनसंख्या बदलाव को लेकर गंभीर जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे गिरोहों पर छापे मारे हैं जो सीमा पार से लोगों को लाकर फर्जी आधार कार्ड और स्थानीय पहचान पत्र तैयार करते थे। ओडिशा ने भी बारह राज्य स्तरीय और उन्नीस जिला स्तरीय निरोध केंद्र बनाकर साफ कर दिया है कि अब घुसपैठ के मामलों में िझाई नहीं बरती जायेगी।

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टुक कहा है कि देश में अवैध घुसपैठ को लेकर शुन्य सहनशीलता की नीति लागू है। सीमा निगरानी मजबूत की जा रही है और हजारों लोग दबाव बढ़ने के बाद स्वेच्छा से वापस लौट रहे हैं। देखा जाये तो यह अभियान केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की निर्णायक लड़ाई है।

बहरहाल, स्पष्ट है कि बंगाल और पूर्वांचल में दशकों से पनपी घुसपैठ की समस्या विस्फोटक रूप ले चुकी थी। लेकिन अब देश का माहौल बदल रहा है। गुजरात का ऑपरेशन, बंगाल की सख्ती, असम का अभियान और पूर्वांचल राज्यों की चेतावनी इस बात का संकेत है कि भारत अब अपनी सीमाओं, अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शने वाला नहीं। घुसपैटियों के खिलाफ चल रहा यह राष्ट्रव्यापी अभियान केवल कानून व्यवस्था की कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा का निर्णायक संघर्ष बन चुका है। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन



मुंगेली । जिला कलेक्टर के प्रति मंगलवार आयोजित होने वाला जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर कुन्दन कुमार के निदेशानुसार आयोजित जनदर्शन में अपर कलेक्टर जी.एल. यादव ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुने तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को सम्बन्धित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में 190 से अधिक नागरिकों ने आवस, सौचालय, पेसन, आधार कार्ड, जन प्रमाण पत्र, विद्युत व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन

प्रस्तुत किए। प्रशासन द्वारा प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जनदर्शन में ग्राम खैरवार के रमेश यादव ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सौचालय निर्माण, ग्राम दुर्गिह बाव को उतार बचेल ने स्थायी जलित प्रमाण पत्र, ग्राम झोंका के रमेश नवरंग ने टैनदयाल उग्रध्वज भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ, ग्राम लैलापुर के भरत लाल साहू ने मरेग नाब कांड, पुन साहू ने रतन काई, ग्राम खन्वरिया को दिव्यंग जैला राय ने निःशुल्क ट्रेडमार्किंग, नगदीश प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा धीरपाल ने समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया।

बड़राजपुर वन परिक्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की कटाई, वन संपदा पर मंडराया खतरा

कोंडगांव। केशकाल वनमंडल के बड़राजपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हरखेल के आश्रित ग्राम तराईवेड़ा एवं आसपास के जंगलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ों को खुलेआम काटा जा रहा है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

जानकारी के अनुसार जंगलों के भीतर ही नहीं, बल्कि कई स्थानों पर सड़क किनारे भी कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गमी और बरसात के मौसम में मकानों की मरम्मत, खपरेल निर्माण तथा अन्य घरेलू जरूरतों के लिए लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण कुछ लोग अवैध रूप से जंगलों से लकड़ी निकाल रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि यदि समय रहते अवैध कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र की हरियाली, जैव विविधता और वन्यजीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

लागतार पेड़ों की कटाई से पर्यावरण संतुलन बिगड़ने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मामले की जांच कर अवैध कटाई में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था



सुनिश्चित करने की मांग की है। अब क्षेत्र में यह सवाल उठ रहा है कि वन विभाग की

बस्तर के आदिवासियों में मौत शोक नहीं उत्सव : अनूठी परंपरा ‘कुंडा नेंग’ और ‘हाना पाटा’ गीत से दी जाती है विदाई

भानुप्रतापपुर। आदिवासी समुदाय अपनी अनूठी संस्कृति, रीति-रिवाज और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। प्रकृति से जुड़े इस समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक के नियम सबसे अलग हैं।

आम तौर पर किसी की मृत्यु होने पर हर तरफ शोक का माहौल होता है, लेकिन बस्तर के आदिवासी समाज में वयस्क या वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर शोक नहीं, बल्कि उत्सव मनाया जाता है। हाल ही में दुर्गकोंदल ब्लॉक के ग्राम दियागांव निवासी सगराम कोमरा की मृत्यु के बाद उनके परिवार द्वारा इसी अनूठी परंपरा ‘कुंडा नेंग’ का निर्वहन किया गया, जिसमें मौत के गम को भुलाकर खेल-नगाड़ों के साथ मृतक की जीवन गाथा का



जसन मनाया गया।

क्या है ‘कुंडा नेंग’ और ‘माई घर’ की मान्यता?: आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रभाग ललित नरेटी ने बताया कि समाज में जब किसी वयस्क व्यक्ति की मृत्यु होती है,

तो उसे बड़ा काम या कुछ नेंग कहा जाता है। यह संस्कार मृत्यु के 10 से 15 दिनों के भीतर किया जाता है। आदिवासी समुदाय का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान खत्म नहीं होता। कुंडा नेंग के माध्यम से मृतक की ऊर्जा

को प्राकृतिक ऊर्जा के साथ समन्वित किया जाता है। इसके बाद उनकी आत्मा या ऊर्जा को मिट्टी की हंडी में रखकर माई घर (खेकरा घर) में स्थापित कर दिया जाता है। समाज की मान्यता है कि इसके बाद उनके पूर्वज हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उनके साथ ही मौजूद रहते हैं। इसी खुशी में खेल बजाकर और नाचकर खुशियां मनाई जाती हैं।

बेटी-बहनें खेल और सूरा सजाकर करती हैं नृत्य: इस संस्कार के दौरान मृतक के परिवार की बेटियां, बहनें और समाधान पक्ष के लोग पारंपरिक खेल और बांस से बने ‘सूरा’ को आकर्षक ढंग से सजाकर नृत्य करते हैं। अंतिम संस्कार के समय से लेकर कुछ संस्कार तक, अलग-अलग समय पर अलग-अलग पारंपरिक गीत गाए जाते हैं।

अंतिम विदाई में शव को पेन मानकर किया जाता है जोहार

आदिवासी समाज की परंपरा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव को पूरा कर दुनिया से जाता है, तो शव को दफनाने से पहले कब्र के पास महिला और पुरुष कतार में बैठ जाते हैं। वहीं शव को ‘पेन’ (देवता) तुल्य माना जाता है। सभी सगाजन और ग्रामवासी मृतक से ‘जोहार’ (भेंट-मुलाक़ात) करने का आग्रह करते हैं। माना जाता है कि इस अंतिम भिलाप के बाद ही शव अपनी कब्र में शांति से जाता है।

नुस हो रह है मृत्यु गीत ‘हाना पाटा’

आदिवासी समाज में हर अवसर के लिए अलग गीत है। सुबह की झुंझुआत गोंडी गीत से होती है और शाम घोंदल में ‘रेल गीत’ के साथ खत्म होती है। इसी तरह, मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला एक विशेष गीत है जिसे ‘हाना पाटा’ (मृत्यु गीत) कहा जाता है। कुंडा संस्कार के दूसरे दिन सुबह जब समाज के लोग जुटते हैं, तो गीतकार मृतक के पूरे जीवन की कहानी को एक विशेष लय-ताल में भिरोकर गाने हैं। हालांकि, आयुष्मित्रा के दौर में यह अनूठी ‘हाना पाटा’ कला और इसके गीत धीरे-धीरे धुंधले होते जा रहे हैं, जिसे सहेजने की आवश्यकता है।

समय सीमा की बैठक : जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें- कलेक्टर नम्रता जैन

सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का सभी विभाग शतप्रतिशत निराकरण गंभीरता पूर्वक कराएँ

नारायणपुर। जिला कार्यालय के समाकक्ष में कलेक्टर नम्रता जैन की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। साथ ही लंबित प्रकरणों पर भी गहन चर्चा करते हुए उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यों में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा से लंबित न रहे।

कलेक्टर नम्रता जैन ने जिले में किसानों को खेती के मौसम के दौरान पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक भंडारण एवं वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण पर नियमित निगरानी रखी जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक में कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का संबंधित विभाग गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ शत-प्रतिशत



निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण कर आवेदकों को त्वरित रहत प्रदान की जाए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर नियमित निरीक्षण करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन शतप्रतिशत कराने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया। समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों का समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं से लाभान्वित करने गांवों में जाकर सर्वे करें। नियद नेख्ननार

योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित मूलभूत सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, उन्हें प्रति सप्ताह निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, पेंशन, वोट आईडी, आयुष्मान कार्ड, आधारकार्ड, बैंक पासबुक और महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं की जानकारी लेने के निर्देश दिए। जिले के पहुंचविहीन क्षेत्रों में बरसात के पहले बरसात के पहले तीन माह का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारी को दिये। समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जानकारी दिया कि 16 जून से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने स्कूल आश्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मलेरिया जांच कराने के निर्देश जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी को दिये। जिले में अब तक जिन्होंने राशनकार्ड को ईकेवाईसी नहीं कराएँ हैं, ऐसे लोगों का शीघ्र ही ईकेवाईसी करने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बस्तर मुन्ने अभियान अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में चल रहे निर्माणधीन कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचमाई, एसडीएम अभयजीत मंडवी, सहायक आयुक्त आर्दवासी विकास डॉ. राजेन्द्र सिंह, सीएमएचओ डॉ. टीआर कुंवर, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल, जनपद सीईओ सुनील कुमार सोनपिप्रे, लोकेश चतुर्वेदी, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

आरक्षक जोगेंद्र नेताम के निधन पर कोंडगांव पुलिस की गहरी संवेदना

कोंडगांव। 08 जून को सुबह लगभग 11:50 से 12:00 बजे के मध्य थाना उरंदवेड़ा में तैनात 5वीं बटालियन, जगदलपुर की ई कंपनी के आरक्षक जोगेंद्र नेताम ने थाना मोर्चा पर ड्यूटी के दौरान अपने



इश्वरशुदा राइफल्स से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया यह घटना पारिवारिक कारणों से हुई प्रतीत होती है। थाना उरंदवेड़ा द्वारा इस प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही शुरू कर दी गई है और पूरे मामले की गहन छनबीन की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कोंडगांव पंकज चन्दा ने आरक्षक जोगेंद्र नेताम के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उनके

परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए अत्यंत दुःखद क्षण है। जोगेंद्र नेताम पुलिस बल का एक समर्पित सदस्य थे। उनके निधन से पूरा कोंडगांव पुलिस परिवार शोक में डूबा हुआ है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभव सहायता एवं समर्थन प्रदान करेंगे। कोंडगांव पुलिस परिवार दिवंगत आरक्षक जोगेंद्र नेताम को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

एएम-एनएस इंडिया कंपनी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर किए गए विविध कार्यक्रम

किरंदुल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आर्सेलर्मितल निप्पन स्टील इंडिया की सीएसआर टीम द्वारा किरंदुल क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम ‘प्रकृति से प्रेरित: जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए’ को केन्द्र में रखते हुए कंपनी ने स्थानीय समुदायों और स्कूली बच्चों को प्रकृति के साथ जुड़ने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस विशेष अवसर पर देतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल ग्राम मड़कामीरास के हाई स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कलेपाल, समलवार, गुमियापाल, कुटरेम, हिरोली और मड़कामीरास ग्राम पंचायतों के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।प्रतियोगिता को कुल चार समूहों में विभाजित किया गया था, जिसमें जूनियर और सीनियर श्रेणियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी कला और कल्पना शक्ति से पर्यावरण संरक्षण का संदेश



कैनवास पर उकेरा। आयोजन के दौरान एएम/एनएस किरंदुल के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, बालाजी और राजेश ठाकुर ने स्कूल का दौरा किया। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाई गई जीवंत कलाकृतियों का निरीक्षण कर उनकी प्रतिभा की सराहना की।इसके पश्चात,

अतिथियों ने मड़कामीरास हाई स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन एक भव्य प्रसूकर वितरण समारोह के साथ हुआ, जहाँ चारों श्रेणियों के शीर्ष तीन विजेताओं को सम्मानित किया गया।

भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य का दंतेवाड़ा में स्वागत अभिनंदन



दंतेवाड़ा। भारतीय मजदूर संघ के छत्तीसगढ़ एवं मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री सी.वी. राजेश एवं राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं उद्योग प्रभारी (नान कोल) दिनेश कुमार पाण्डेय के दंतेवाड़ा प्रवास पर भारतीय मजदूर संघ के दक्षिण बस्तर प्रभारी रूद्र प्रताप ताती एवं खदान मजदूर संघ

शाखा किरंदुल, बचेली के पदाधिकारियों द्वारा आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया। स्थानीय सर्किट हाउस में भारतीय मजदूर संघ की महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिचर्चा की गई एवं ट्रेड यूनियन की मजबूती हेतु क्षेत्र संगठन मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर

खदान मजदूर संघ शाखा किरंदुल के अध्यक्ष बी. दिलीप राव, उपेन्द्रनाथ त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत पोयाम, एस. के. मल्लिक, बचेली शाखा के अध्यक्ष पूरन दास, सचिव वी.एस. सुभाषचंद्र बोस, राजेश तामो, जी. नारसैय्या, धीरेन्द्र देवमुख, जयराम जॉनसन उपस्थित थे।

नगर पालिका नारायणपुर में 12 जून को स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

नारायणपुर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के 06 वर्ष पूर्ण होने पर जून से 30 जून 2026 तक संपूर्ण देश में पीएम स्वनिधि विशेष अभियान के तहत जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सव, शेष नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेला एवं जनगणना शहरों में स्वनिधि कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पथ विक्रेताओं, शहरी गरीबों एवं असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेश, डिजिटल सशक्तीकरण एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों से जोड़ना है। यह महोत्सव समर्पित पथ विक्रेता केन्द्रित आउटरीच कार्यक्रम है जो कि पथ विक्रेताओं के लिए सूक्ष्म ऋण प्रहंच, डिजिटल सशक्तीकरण एवं सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करेगा। इसी तारतम्य में रामचन्द्र यादव मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद नारायणपुर ने बताया कि शासन की महत्वकांक्षी

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना से पथ विक्रेताओं, शहरी गरीबों एवं असंगठित श्रमिकों के हितार्थ नगरपालिका परिषद नारायणपुर में भी 01 जून 2026 से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक- 12 जून 2026 को नगरपालिका नारायणपुर के सभाकक्ष में बृहत स्तर पर जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस योजना के प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशन, शहर क्षेत्र में होर्डिंग, लाकड स्पीकर के माध्यम से मुनादी, पाम्पलेट के माध्यम से तथा सीधे सम्पर्क स्थापित कर पथ विक्रेताओं, असंगठित श्रमिकों एवं शहरी गरीबों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। योजना में सूक्ष्म ऋण के तहत प्रथम ऋण- 15000 रुपये, द्वितीय ऋण- 25000 रुपये एवं तृतीय ऋण- 50000 रुपये प्रदाय किया जा रहा है तथा डिजिटल सशक्तीकरण क्रेडिट कार्ड एवं डिजिटल भुगतान के बारे में भी बताया जा रहा है निश्चित ही इस महोत्सव से पथ विक्रेताओं, शहरी गरीबों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।



संक्षिप्त समाचार

वर्षा ऋतु के दौरान मत्स्याखेट पर लगा प्रतिबंध

बिलासपुर। जिले में आगामी वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंधित लगाया गया है। उप संचालक मछली पालन ने बताया कि जिले के सभी तालाबों एवं जल स्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध होने पर 25 हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कोनी में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 11 से

बिलासपुर। शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कोनी में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 11 जून 2026 से प्रारंभ की जा रही है। 10वीं उत्तीर्ण एवं पीपीटी परीक्षा में शामिल छात्राएं काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होकर प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन 11 जून सवेरे 10 बजे से 15 जून 2026 रात्रि 11.59 बजे तक किया जा सकेगा। मेरिट सूची 16 जून को शाम 5 बजे जारी होगी तथा दावा-आपत्ति 17 जून रात्रि 11.59 बजे तक स्वीकार की जाएगी। प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया 20 जून सवेरे 10 बजे से 24 जून 2026 शाम 5.30 तक संपन्न होगी। द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन 26 जून सवेरे 10 बजे से 30 जून रात्रि 11.59 बजे तक होगा। मेरिट सूची 1 जुलाई को शाम 5 बजे जारी की जाएगी तथा दावा-आपत्ति 2 जुलाई रात्रि 11.59 बजे तक प्रारंभ किये जाएंगे। द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक चलेगी। संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन 11 जुलाई सवेरे 10 बजे से 16 जुलाई 2026 रात्रि 11.59 तक किये जा सकेगा। इसकी मेरिट सूची 17 जुलाई को शाम 5 बजे जारी होगी तथा प्रवेश प्रक्रिया 18 जुलाई सवेरे 10 बजे से 22 जुलाई 2026 बजे तक संपन्न की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट का अवलोकन सकते हैं। अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीयन करने तथा चॉइस फिलिंग सावधानीपूर्वक भरने की अपील की गई है।

तेज रफ्तार पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर, पांच माह में 14,372 वाहन चालकों को भेजी नोटिस

बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस बिलासपुर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफसख्त अभियान शुरू कर रखा है। अत्याधुनिक स्पीड डिटेक्टर कैमरों, एएनपीआर तकनीक और इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से जिलेभर में निगरानी की जा रही है। जनवरी से मई 2026 तक यातायात पुलिस ने 14,372 प्रकरण दर्ज कर संबंधित वाहन चालकों को नोटिस जारी की है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस विशेष रूप से उन उल्लंघनों पर फोकस कर रही है, जो गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। यातायात पुलिस के अनुसार, जिले में इंटरसेप्टर, स्पीड राडार गन और स्पीडोमीटर के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति की निगरानी की जा रही है। वहीं शहर के भीतर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) से जुड़े 550 से अधिक अत्याधुनिक कैमरे चौक-चौराहों और प्रमुख मार्गों पर नजर रख रहे हैं। पुलिस ने बताया कि शहर का लगभग पूरा क्षेत्र एएनपीआर कैमरों की निगरानी में है। इन कैमरों के जरिए तय गति सीमा से अधिक रफ्तार, खतरनाक स्टैंट, रील बनाते हुए वाहन चलाने, जोखिमपूर्ण ड्राइविंग और अन्य गंभीर यातायात उल्लंघनों की पहचान कर ऑनलाइन चालान और नोटिस भेजी जा रही हैं।

भटके दंतैल हाथी ने दंपति को कुचला, गांव में दहशत

बलरामपुर। जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। राजपुर वन परिक्षेत्र के कुंदीकला गांव में एक भटके हुए दंतैल हाथी ने पति-पत्नी पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में दहशत और मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार, दंपति सुबह करीब पांच बजे घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान बांधेपारा जंगल के समीप उनका सामना एक दंतैल हाथी से हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथी ने अचानक हमला कर दोनों को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कल्याणपुर क्षेत्र में पांच हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है।

पंचायत विकास योजना एवं पंचायत उन्नति सूचकांक के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण आयोजित किया

ग्राम विकास की प्राथमिकताओं, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर हुई विस्तृत चर्चा

बिलासपुर। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त एवं विकासोन्मुख बनाने के उद्देश्य से आज क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण-सह-समीक्षा बैठक में पंचायत विकास योजना (वृहत्) एवं पंचायत उन्नति सूचकांक (ब्रह्म) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की 7बैठक के दौरान ग्राम पंचायतों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं के निर्माण, प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा पंचायत उन्नति सूचकांक के विभिन्न मानकों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि



पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी एवं परिणाममूलक बनाया जा सकता

है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएलडब्ल्यूएम (स्वच्छ) 2026 नियमों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने समस्त ग्राम पंचायतों में नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पहल

करने पर जोर दिया। साथ ही स्वच्छ गांव-स्वस्थ गांव अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त ग्राम निर्माण तथा जनसहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में पंचायत उन्नति सूचकांक के विभिन्न संकेतकों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को विकास कार्यों में अतिरिक्त अवसर एवं प्रोत्साहन प्राप्त हो सकते हैं। अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग तथा ग्राम विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक के अंत में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा ग्राम विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण से संबंधित सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत बिल्हा एवं मस्तूरी के जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, अधिकारी-कर्मचारी तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ग्राम विकास की प्राथमिकताओं, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर हुई विस्तृत चर्चा

ग्रादेशिकी

गांव-गांव पहुंचा संरक्षा का संदेश

अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता सप्ताह अभियान का चतुर्थ दिवस

बिलासपुर मंडल की अभिनव पहल : ग्रामीणों को रेल लाइन, समपार फ़टक एवं पशुधन सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

रेल लाइनों के निकट बसे 54 से अधिक गांवों में आयोजित हुए जनसंवाद कार्यक्रम

बिलासपुर। अंतरराष्ट्रीय समपार जागरूकता सप्ताह-2026 के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा समपार सुरक्षा एवं रेलवे संरक्षा के प्रति जनजागरूकता फैलाने हेतु व्यापक जनसंवाद एवं ग्राम संपर्क अभियान

संचालित किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री साकेत रंजन के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज मंडल के विभिन्न समपार फ़टकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के अंतर्गत आज बिलासपुर मंडल के विभिन्न रेलखंडों में स्थित 54 से अधिक गांवों एवं बस्तियों में जनसंवाद एवं ग्राम संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 8600 से अधिक ग्रामीण नागरिकों, वाहन चालकों, विद्यार्थियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नागरिकों को समपार फ़टकों को सुरक्षित रूप से पार करने, रेल लाइन के समीप सतर्कता बरतने तथा सुरक्षित रेल संचालन में जनभागीदारी के महत्व के संबंध में जागरूक किया। अभियान के दौरान



बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सकी, रायगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, पेंड्रा-मरवाही, कोरिया-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर एवं सुंदरगढ़ जिलों के अंतर्गत आने वाले अनेक गांवों एवं बस्तियों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से इमलीछाप, विकास नगर, फ़ोकटपारा, संजय नगर, रामसागर पारा, अमरैया पारा,

भिलाईखुर्द, बरबसपुर, लालमाटी, पटायड़ी, पहंदा, बंधुआभाठा, बरपाली, धुलेना, मदवा बस्ती, लोनपुर, कोठारी बस्ती, सुहागपुर, जनमिपाली, रीवापार/बालपुर, शिवनी बस्ती, चैनपुर, साल्ही, लालपुर, भरीला, अमहा एवं सिमरिया सहित अनेक गांवों में ग्रामीण नागरिकों को रेलवे सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों को समपार फ़टकों को

सुरक्षित रूप से पार करने, रेल लाइन के समीप सतर्कता बरतने, बच्चों एवं पशुओं को रेलवे ट्रैक से दूर रखने तथा रेलवे ट्रैक के आसपास किसी भी प्रकार की असुरक्षित गतिविधि से बचने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। नागरिकों को यह भी बताया गया कि रेलवे ट्रैक पर चलना, ट्रैक को शॉर्टकट के रूप में उपयोग करना अथवा समपार फ़टक बंद होने पर जल्दबाजी में उसे पार करने का प्रयास गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। ग्रामीणों को विशेष रूप से यह समझाया गया कि रेलवे ट्रैक के निकट कूड़ा-कचरा अथवा खाद्य सामग्री फेंकने से पशु ट्रैक की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे रेल एवं पशु दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। उपस्थित ग्रामीणों से अपने पशुधन की निगरानी रखने, मवेशियों को रेलवे ट्रैक एवं समपारों से दूर रखने तथा रेलवे संरक्षा में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई।

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण



ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से अवलोकन किया तथा वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और उपचार व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा कर मरीजों को दी जा रही सेवाओं और अस्पताल संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.पी. सिंह ने केंद्रीय राज्यमंत्री को बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन

औसतन 120 से 150 मरीज ओपीडी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। इसके अतिरिक्त आईपीडी में भर्ती मरीजों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया।

घरेलू महिलाओं से बनीं सफल उद्यमी.....राधा कृष्ण महिला समूह की दीदियां बनीं लखपति

ग्राम बेलपान की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की लिखी नई इबारत



की महिलाओं ने हल्दी, मिर्च एवं मसाला निर्माण के साथ-साथ मुरकू और पापड़ निर्माण का कार्य शुरू किया। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और निरंतर मेहनत के बल पर व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ा और समूह को नियमित आय मिलने लगी। आज समूह की प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह लगभग 45,000 से 50,000 रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। इस प्रकार समूह की वार्षिक आय लगभग 5 लाख 40 हजार रुपये तक पहुंच गई है। बढ़ी हुई आय से सदस्यों के परिवारों की

आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की बेहतर ढंग से पूर्ति कर पा रही हैं। समूह की महिलाएं बताती हैं कि पहले गांव में उनकी कोई विशेष पहचान नहीं थी, लेकिन आज वे आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में जानी जाती हैं। उनकी सफलता ने गांव की अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आजीविका गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

रोजगार मेले में 122 युवाओं का चयन, 234 अभ्यर्थी प्रारंभिक रूप से चयनित



युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सफल पहल

बिलासपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, कोनी, बिलासपुर द्वारा आयोजित रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रोजगार मेले में विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों द्वारा कुल 653 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। मेले में 935 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीयन कराया, जिनमें से 687 आवेदक उपस्थित हुए। साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के बाद 234 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन तथा 122 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया। रोजगार मेले का निरीक्षण संभागयुक्त सुनील जैन एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न नियोजक संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा रोजगार की तलाश में पहुंचे युवाओं से चर्चा कर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। अधिकारियों ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए अन्य युवाओं को भी अपने कौशल का विकास कर रोजगार के अवसरों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। संभागयुक्त

श्री सुनील जैन ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं और उद्योग जगत के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। युवाओं को बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वे प्रतिस्पर्धी वातावरण में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने रोजगार मेले में शामिल नियोजक संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने में सहायता मिलती है। श्री अग्रवाल ने युवाओं से अपने कौशल और क्षमता को लगातार विकसित करने तथा उपलब्ध रोजगार अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 वाहन चालको पर लगा 4,900 रुपये समन शुल्क



बेमेतरा। पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एका, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी कौशल्या साहू, डीएसपी शशीकला उर्डिके के मार्गदर्शन में समस्त थाना/चौकी, व यातायात बेमेतरा पुलिस टीम द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, भारी वाहन, तेज गति से वाहन चलाना, दोपहिया पर मोडिफाई साइलेंसर तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चौकी 01 मारो में 01 वाहन चालको, यातायात बेमेतरा 14 चालान में 14 वाहन चालको, कुल 15 वाहन चालको के विरुद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जैसे तीन सवारी, बिना सीट बेल्ट, माल वाहक में सवारी बैठाना, तेज गति, घातक तरीके से वाहन खड़ी करना, मौके पर कागजात पेश न करना, बिना लायसेंस वाहन चालको के विरुद्ध 15 प्रकरण में 4,900/- रुपये समन शुल्क लिया गया। बेमेतरा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं तथा वाहन चलते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। वाहन चलाने समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करें तथा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें।

शक्ति केंद्र किरगी में अर्जुनी मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष सहित दोनों महामंत्री रहे मौजूद



डोंगरगांव नगर। अर्जुनी भाजपा मंडल की मासिक बैठक शक्ति केंद्र किरगी में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता, मंडल प्रभारी कैलाश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री के मंत्रानुरूप संगठन के लिए समर्पित होकर योगदान देने अपील की। प्रभारी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए नियमित संपर्क,

बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़! सक्षम आंगनबाड़ी योजना में अनियमितता की आशंका

बेमेतरा। महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वाकांक्षी सक्षम आंगनबाड़ी उष्यन योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की आशंका सामने आई है। योजना के तहत प्रत्येक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के लिए लगभग 61 हजार रुपये की राशि एलईडी टीवी, आरओ वाटर फ़िल्टर, वॉल पेंटिंग तथा रैन वाटर हार्वैस्टिंग इंस्टॉलेशन जैसे कार्यों के लिए प्रदान की गई थी। बेमेतरा परियोजना के अंतर्गत कुल 20 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से शहरी क्षेत्र की 6 आंगनबाड़ियों का जानकारी चाही गई और उन सभी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं से बात भी की गई जिससे यह पता चला कि 1 से 2 केंद्रों में संप्रवतः निर्धारित कार्य पूर्ण पाए गए, जबकि कई केंद्रों में केवल एलईडी टीवी और पानी की टंकी ही स्थापित मिली। तो कहीं वॉल पेंटिंग और रैन वाटर हार्वैस्टिंग जैसे कार्य अधिकांश स्थानों पर नहीं दिखाई दिए। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठने लगे हैं कि यदि शासन द्वारा चार्ज कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, तो फिर कई केंद्रों में सभी सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं हैं। इससे योजना की राशि के उपयोग को लेकर संदेह की स्थिति बन रही है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सिरोजिया से उनका पथ जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उनके ऑफिस में जाकर भी सम्पर्क करने का प्रयास किया गया मगर वो वहां पर भी



नहीं मिले शायद किसी मीटिंग या अन्य कार्य की जानकारी दिया गया उनके ऑफिस स्टॉप के द्वारा। गौरतलब है कि सक्षम आंगनबाड़ी योजना का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि स्वीकृत कार्य अधूरे पाए जाते हैं तो यह मामला जांच का विषय बन सकता है। क्योंकि जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले में कई परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं के अन्तर्गत कई सक्षम आंगनबाड़ी आते हैं क्योंकि मात्र बेमेतरा परियोजना के अंतर्गत 20 सक्षम आंगनबाड़ी आते हैं तो जिले के अंतर्गत कितने सक्षम आंगनबाड़ी आते होंगे इसकी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

विषय पर आधारित कक्षा सातवीं के नवीन पाठ्य पुस्तक व एफएलएन प्रशिक्षण पर डाइट में बनी कार्ययोजना

बेमेतरा। विषय पर आधारित नवीन पाठ्य-पुस्तक प्रशिक्षण कक्षा 7 वी एवं एफएलएन नवीन पाठ्य-पुस्तक प्रशिक्षण प्रारंभिक विद्यालय पहले चरण में 5 दिवस और 2 दिवस असाइनमेंट पर कार्य करने के बाद कुल 7 दिवस आनलाईन प्रशिक्षण होगा। यह प्रशिक्षण 11 जून से प्रारंभ होगा। विषय आधारित आनलाईन प्रशिक्षण हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान तथा प्राथमिक स्तर पर गणित, भाषा, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, खेल एवं योग कला एवं योग शिक्षा विकास खंड स्तर पर आयोजित होगा। यह आनलाईन प्रशिक्षण 10-5 बजे के बीच आयोजित किया जाना है। यह प्रशिक्षण बैच में ही किया जाएगा। एक बैच में अधिकतम 65 शिक्षकों को



प्रशिक्षित किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में जिला के चारों विकास खंड बेरला, बेमेतरा, साजा, नवागढ़ में चार चार जेन में प्रशिक्षण आनलाईन दिया जाएगा। जिसमें प्रत्येक जेन में 3-3 बीआरजी प्रशिक्षण देंगे। जिसकी माॉनटरिंग जिला व विकास खंड के अधिकारियों, डाइट के अकादमिक सदस्यों के द्वारा नियमित माॉनटरिंग किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर डीआरजी, अजीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन द्वारा सभी जेन की प्रशिक्षणों में सहयोग

सुशासन तिहार के समाधान शिविर में उमड़ा जन विश्वास, शासन की योजनाओं का मिला सीधा लाभ

विधायक दीपेश साहू ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान



बेमेतरा। मुख्यमंत्री कृष्णदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत लाटा में विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में

वैलस्टर की विभिन्न ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक

निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर रजककार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल, प्रदेश मंत्री संघ्या परानिहा, रायपुर जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री पोषण वर्मा, मंडल अध्यक्ष सूर्यकांत नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि योगेश तिवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विधायक दीपेश साहू ने अपने संबोधन में कहा

36 मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का सम्मान रहा। वलस्टर क्षेत्र के 36 मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विधायक दीपेश साहू ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा ही विकास का सबसे सराफ माध्यम है और यही विद्यार्थी क्षेत्र एवं प्रदेश का भविष्य हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर अध्ययन, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विधायक दीपेश साहू ने बताया कि युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेमेतरा में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक नाला पारसर का निर्माण कराया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रीराम एकेडमी के माध्यम से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है तथा शीघ्र ही श्रीराम लाइब्रेरी का शुभारंभ भी किया जाएगा।

बालोद जिले में पीएम आवास योजनांतर्गत कुल 3077 लाभार्थियों के किशतों की राशि कुल 9.53 करोड़ स्वीकृत

बल्लरीराजहरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि केंद्रीय और राज्यांश मद से एसएनए स्पर्श मांड्युल के माध्यम से आवंटित की गई है, जिससे पात्र हितग्राहियों के घर समय पर और पारदर्शी तरीके से बन सकें। इसी क्रम में बालोद जिले में पीएम आवास योजनांतर्गत कुल 3077 लाभार्थियों के किशतों की राशि कुल 9.53 करोड़ रुपए के अंतरण हेतु एसएनए स्पर्श मांड्युल पर एफटीओ साईन किया गया है। यथाशीघ्र जिले के लाभार्थियों को किशतों की राशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित होंगे, जिससे योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सकेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में कुल

रातापायली पुल के दोनों छोर एप्रोच रोड ध्वस्त पुल से आवागमन बंद, नदी में चल रहे राहगीर

बारिश सीजन के करीब तोड़फोड़ से जनाक्रोश



विद्यार्थियों व मरीजों को दिक्कत
पुल आवागमन बंद हो जाने से मरीजों को वही में पैदल चलकर आवाजाही करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल के छात्र किरगी या रुद्रगांव की ओर से आवाजाही करते मजबूर हैं। वहीं आगामी पखवाड़ेभर में स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों को भी दिक्कत आने के आसार बज रहे हैं। क्षेत्र के गाजपहई बिस्नेस साहू एवं उज्जय वैष्णव ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।

डोंगरगांव नगर। ब्लॉक के ग्राम रातापायली में शिवनाथ नदी स्थित पुल के दोनों छोर के एप्रोच को ध्वस्त कर दिया गया। पुल में एक साथ दोनों छोर को ध्वस्त कर देने पुल में आवागमन पूर्णतः बंद हो गया है। बारिश के ऐसे वक्त पहले ही एप्रोच ध्वस्त कर देने से क्षेत्र के ग्रामीण, किसान व राहगीर चौड़ी नदी में पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजगीरों ने मीडिया को बताया कि लगभग 4 दिनों पूर्व ही शनिवार से पुल के दोनों छोर को एक साथ ध्वस्त कर दिया गया है, मौके पर मौजूद एप्रोच में तोड़फोड़ कर रहे कामगारों ने एप्रोच में बड़ी दरारें आने की वजह से मरम्मत करने हेतु एप्रोच ध्वस्त करने की बात बता रहे हैं, हालांकि जनाक्रोश के महेनजर ठेकेदार का संपर्क नंबर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कामगारों ने बताया कि ठेकेदार संतोष साहू, भिलाई निवासी है। कामगारों की माने तो मरम्मत करने में लगभग 15 से 25 दिन लग जायेंगे। यानि बारिश के मौसम करीब होने अथवा बारिश होने की स्थिति में कार्य प्रभावित होने पर मरम्मत कार्य में लेटवारीफे हो सकती है। ऐसी स्थिति में बारिश सीजन में क्षेत्र के लगभग 15 से अधिक गांवों के ग्रामीणों का रातापायली की ओर से आवागमन बंद हो जाने के आसार हैं।

पौधा लगाना नहीं, पेड़ बनाना है साहू समाज का लक्ष्य



बल्लरीराजहरा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 7 जून को तहसील साहू संघ दल्ले राजहरा ने न्यू बस स्टैंड के पास तहसील साहू सदन के सामने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस बार का पौधारोपण सिर्फरसम अदायगी नहीं था, बल्कि पौधे से पेड़ बनने तक की जिम्मेदारी का संकल्प था। तहसील साहू संघ अध्यक्ष शीतल साहू ने बताया कि प्रदेश साहू संघ के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें शूद्ध हवा-पानी मुफ्त में देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। हमारा भी फर्ज बनता है कि प्रकृति को सहेजकर रखें। इसी सोच के साथ साहू सदन के सामने करंज का पौधा रोपा गया। करंज का चयन सोच-समझकर किया गया क्योंकि बड़ा होकर यह घनी छाया तो देता ही है, साथ ही

लोक नृत्य कलाकार विजय बोरकर विजय बोरकर श्रीलंका में देंगे प्रस्तुति



बल्लरीराजहरा। छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दल्लेराजहरा के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार विजय बोरकर श्रीलंका खाना हो चुके हैं। वे 9 से 13 जून 2026 तक कैडी, श्रीलंका में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल डॉस एंड म्यूजिक ओलंपियाड फेस्टिवल 2026 में अपनी लोक नृत्य प्रस्तुति देंगे। दल्लेराजहरा नगर में जन्मे विजय बोरकर वर्ष 2005 से नृत्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने मॉडर्न डॉस रूप संस्था के माध्यम से न केवल स्कॉच मंचों पर उल्कू प्रस्तुतियां दी हैं, बल्कि सैकड़ों बच्चों को लोक एवं सांस्कृतिक नृत्य का प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। उनके प्रशिक्षण से अनेक प्रतिभाएं कला जगत में अपनी पहचान बना चुकी हैं। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर विजय बोरकर छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, विशेष रूप से बस्तर एवं पारंपरिक लोक नृत्य की झलक प्रस्तुत करेंगे। बालोद जिले से लोक नृत्य विधा में इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागिता में भाग लेने वाले वे

सीड बॉल अभियान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। गोबर एवं मिट्टी से तैयार सीड बॉलस में विभिन्न पौधों के बीज डालकर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से बड़े पैमाने पर वितरण किया गया। इस पहल ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया तथा बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित की। ग्रौमफालीन अवकाश के दौरान भी उन्होंने विद्यालय विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा। विद्यालय धवन की मरम्मत, रंग-रोगन, स्वच्छता एवं परिसर सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाकर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालय को आकर्षक एवं शिक्षण अनुकूल बनाया। विद्यालय के प्रति उनके समर्पित भाव और उनके उल्कू कार्यों के आधार पर ही अम्बालिका पटेल को पिछले वर्ष जिले के सर्वश्रेष्ठ प्रधान पाठक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज शासकीय प्राथमिक शाला साल्हेपुर स्वच्छता, हरियाली, सामुदायिक सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं पर्यावरणीय गतिविधियों के कारण क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है।



सुनिश्चित की गई। विद्यालय के भौतिक विकास के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जनसहयोग से बच्चों को अतिरिक्त हेस, टाई, आई-काई एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। विद्यालय में नवाचार आधारित शिक्षण वातावरण विकसित किया गया, जिससे बच्चों की उपस्थिति एवं सीखने की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अंबालिका पटेल द्वारा संचालित